



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2009/ज्येष्ठ 1, 1931

No. 188]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2009/JYAISTHA 1, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2009

अंतिम जांच परिणाम

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन-सी के आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच (निर्णायक समीक्षा)।

सं. 15/16/2008-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क या आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. यतः 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 तथा सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन-सी (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) जो उप-शीर्ष सं. 293627 के अंतर्गत वर्गीकृत है, के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की थी। प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम दिनांक 13 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं. 14/14/2002-डीजीएडी द्वारा अधिसूचित किए गए थे और राजस्व विभाग की दिनांक 24 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं. 159/2003 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. लागू शुल्कों के अधिरोपण को जारी रखने की आवश्यकता और यह पता लगाने के लिए कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 2006 के डब्ल्यू सी सं. 16893 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप में सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(5) तथा नियमावली के नियम

23 के अनुसार दिनांक 23 मई, 2008 को चीन जन गण के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित विटामिन - सी के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत की। घरेलू उद्योग ने इस आधार पर कि चीन जन गण से लगातार पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वर्तमान में क्षति हो रही है और शुल्क की समाप्ति से उसे और अधिक क्षति होगी, पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की माँग करते हुए सूचना प्रस्तुत की। घरेलू उद्योग की ओर से मै0 अमोली ऑर्गेनिक्स प्रा0 लि0 और मै0 बजाज हेल्थ केयर लि0 द्वारा सूचना प्रस्तुत की गई थी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जाँच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है:-

(i) समीक्षा जाँच की शुरुआत के बाद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को सूचना भेजी और उनसे अधिसूचना जारी होने के 40 दिनों के भीतर सूचना की माँग की। घरेलू उद्योग से सूचना प्राप्त होने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उन्हें जारी पत्र के 40 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

(ii) नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को पत्र जारी होने के 40 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र (प्रश्नावली का उत्तर) में सूचना प्रस्तुत करने तथा आवश्यक सूचना प्रदान करने हेतु सूचित किया गया।

(iii) किसी भी निर्यातक ने निर्धारित समय में प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया। अतः उन्हें असहयोगी निर्यातक माना गया है।

(iv) नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को नियम 6(2) के अनुसार जाँच की शुरुआत के बारे में सूचना दी गई और उनसे यह अनुरोध किया गया कि वह अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावली का जवाब निर्धारित समय के भीतर देने की सलाह दें;

(v) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना माँगते हुए भारत में सम्बद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों तथा उपभोक्ताओं को आयातक प्रश्नावलियों के साथ जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रति भेजी गई और उनसे उन्हें जारी पत्र के 40 दिनों के भीतर आवश्यक सूचना की माँग की गई।

(vi) उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में किसी भी आयातक या प्रयोक्ता ने अनुमत समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। अतः उन्हें असहयोगी आयातक/प्रयोक्ता माना गया है।

(vii) संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों ने जाँच हेतु अपनी लागत एवं क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है:-

मै0 अमोली ऑर्गेनिक्स प्रा0 लि0

मै0 बजाज हेल्थ केयर लि0

(viii) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण हेतु विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल उपलब्ध रखी और उसे सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए निरीक्षण हेतु खुला रखा;

(ix) प्राधिकारी ने सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर क्षति की जाँच करने तथा उत्पादन की ईष्टतम लागत एवं भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत निकालने तथा यह निर्धारित करने के लिए कि यदि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा, संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया;

(x) नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से सुनने के लिए 3.2.2009 को सार्वजनिक सुनवाई की। सार्वजनिक सुनवाई में अपना मत प्रकट करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का अनुरोध किया गया था।

(xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों एवं अभ्यावेदनो पर वर्तमान जाँच के संगत सीमा तक विचार किया है।

(xii) पाटनरोधी नियमों के नियम 16 के अनुसार इन जाँच परिणामों में विचार किए गए आवश्यक तथ्यों/आधारों को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट किया गया था और उन पर प्राप्त हुई टिप्पणियों पर इस जाँच परिणाम में विचार किया गया है।

(xiii) वर्तमान जाँच की प्रक्रिया के दौरान जहाँ कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना होने से मना किया है या सूचना प्रस्तुत नहीं की है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने नियम 6 (8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज किए हैं।

(xiv) वर्तमान जाँच हेतु जाँच अवधि 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक की है। तथापि, क्षति विश्लेषण वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 तथा जाँच अवधि के लिए किया गया है।

(XV) *** यह चिह्न इस अधिसूचना में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अनुसार उसे गोपनीय ही माना है।

ग. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

4. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु के संबंध में निम्नानुसार निवेदन किया है:-

(i) वर्तमान जाँच के समीक्षा जाँच होने के कारण विचाराधीन उत्पाद मूल जाँच में दी गई परिभाषा के अनुसार ही रहेगा। इस अवधि में उत्पाद में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ii) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु आयातित उत्पाद के समान वस्तु है।

ग.2 आयातकों, उपभोक्ताओं, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

5. किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता या अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के संबंध में कोई टिप्पणी या निवेदन नहीं किया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

6. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद विटामिन - सी है। जैसा कि प्रविष्टि सं० "मर्क सूचकांक का 867" के अंतर्गत उल्लेख किया गया है, विटामिन - सी के सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले समानार्थक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एल - जाइलोएस्कॉर्बिक एसिड, 3 - ऑक्सो - एल - ग्युलोफ्युरेनोलैक्टोन (इनॉल रूप), एल - 3 - कीटोथ्रियोहेक्स्युरॉनिक एसिड लैक्टोन आदि। यह उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 2936.27 तथा भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार उप शीर्ष 29362700 के अंतर्गत वर्गीकृत है। तथापि, सीमाशुल्क एवं आई टी सी एच एस वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। इस उत्पाद का उपयोग भेषज एवं गैर-भेषज उद्योग में किया जाता है। इस जाँच के निर्णायक समीक्षा होने के कारण विचाराधीन उत्पाद के दायरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

7. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विटामिन - सी तथा चीन जन गण से निर्यातित विटामिन - सी, जिसका कीमत पर प्रभाव पड़ सकता है, में कोई विशेष अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विटामिन - सी भौतिक एवं रसायनिक गुणधर्म, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। अतः घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित एवं चीन जन गण से आयातित विटामिन - सी को पाटनरोधी नियमों के अनुसार समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग

8. वर्तमान याचिका मै0 अमोली ऑर्गेनिक्स प्रा0 लि0, मुम्बई तथा मै0 बजाज हेल्थ केयर लि0, मुम्बई द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह नोट किया गया है कि पूर्व में मूल जाँच में अम्बालाल साराभाई आवेदक थे। तथापि, इस कंपनी ने वर्तमान निर्णायक समीक्षा पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार मै0 अमोली ऑर्गेनिक्स प्रा0 लि0, मुम्बई तथा मै0 बजाज हेल्थ केयर लि0, मुम्बई इस उत्पाद के एकमात्र उत्पादक हैं। चूँकि भारतीय उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 100 प्रतिशत है, अतः वे नियम 2 (ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं।

ड. गोपनीयता

9. मुख्य रूप से ग्राहकों, लागत एवं वित्त के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना को गोपनीय रखा गया है। तथापि समग्र रूप से घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा, उत्पादन, क्षमता आदि संबंधी सूचना को गोपनीय नहीं माना गया है।

च. अन्य मुद्दे**च.1 सार्वजनिक सुनवाई और प्रकटीकरण विवरण के बाद हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे**

10. निर्णायक समीक्षा की शुरुआत के बाद किसी भी निर्यातक, आयातक अथवा हितबद्ध पक्षकार ने जाँच शुरुआत का उत्तर नहीं दिया है और कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। तथापि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान आयातकों सहित अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया। तत्पश्चात् आयातक तथा औद्योगिक प्रयोक्ता होने का दावा करने वाले मै0 पीरामल हेल्थकेयर लिमिटेड (पी एच एल) ने आयातक प्रश्नावली का उत्तर दिनांक 10 फरवरी, 2009 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत की गई सूचना से यह नोट किया गया कि उन्होंने अपने निवेदन में आयातों के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

11. दिनांक 10.2.2009 को श्री एम एन झा, अधिवक्ता ने मै0 नॉर्थ ईस्ट जनरल फार्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेड, चीन की ओर से एक निवेदन प्रस्तुत किया था। श्री एम एन झा के पक्ष में दिनांक 3.2.2009 को किए गए प्राधिकार की एक फोटोप्रति भी संलग्न की गई थी। उनके निवेदन में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में कुछेक टिप्पणियों की गई हैं। चूँकि मूल प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया अतः निवेदनों को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। प्रकटीकरण विवरण के बाद कम्पनी ने यह कहा कि मूल प्राधिकार प्रस्तुत न किया जाना एक सुयोग्य अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत वैध निवेदन को अस्वीकार करने का एक अनुचित आधार है। अधिवक्ता प्राधिकारी के समक्ष स्पष्टीकरण देने के लिए उपलब्ध थे और उनसे प्राधिकार पत्र की मूल प्रति के बारे में नहीं पूछा गया था। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिवक्ता अपने पक्षकार की ओर से निवेदन कर सकता है, वैध प्राधिकार पत्र के बिना कोई निवेदन करना वैध नहीं माना जा सकता। तथापि प्राधिकारी ने कम्पनी की टिप्पणियों में किए गए उल्लेख के अनुसार आंकड़ों को सही कर लिया है।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पी एच एल ने निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं की है अतः उसे सहयोगी आयातक नहीं माना जा सकता ; तथापि उठाए अन्य कानूनी एवं तथ्यात्मक मुद्दों का विवेचन इस जांच परिणाम में यथास्थान किया गया है ।

13. मेसर्स पीरामल हेल्थकेयर लिमिटेड ने निम्नलिखित निवेदन किए हैं:-

(i) यह उत्पाद राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) के अंतर्गत नियंत्रित है । जांच अवधि के दौरान एन पी पी ए ने दिनांक 27.7.2007 की अपनी अधिसूचना संख्या 1280 (ई) द्वारा इस उत्पाद का मूल्य निर्धारण 366 रुपये/किग्रा. किया था ।

(ii) भेषज उद्योग में उपयोग के प्रयोजनार्थ इस उत्पाद का आयात केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (पंजीयन प्रमाण पत्र प्रारूप 41) के अंतर्गत नियंत्रित है । किसी विदेशी विनिर्माता को बिना विशिष्ट अनुमति के इस उत्पाद का आयात एवं भेषज उद्योग द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । यह विशिष्ट अनुमति केवल एक उत्पादक अर्थात् मै0 नॉर्थ ईस्ट जनरल फार्मास्युटिकल कंपनी लि0, चीन को पहली बार प्रदान की गई थी, जो दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 से इस उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं । इससे पूर्व भेषज उद्योग द्वारा अंतिम उत्पाद में उपयोग हेतु संबद्ध वस्तु की खरीद स्थानीय तौर पर अथवा जापान एवं यूरोप से की जा रही थी ।

(iii) पी एच एल को अनुमति (औषधि अधिनियम के अंतर्गत प्रपत्र 9 एवं प्रपत्र 10) माह नवम्बर, 2008 में प्राप्त हुई थी । पी एच एल द्वारा आयात केवल दिसम्बर, 2008 में किए गए, जो स्पष्ट रूप से जांच अवधि के बाहर है ।

(iv) भेषज उद्योग द्वारा विटामिन सी के उपयोग पर नियंत्रण आयात लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता है जिसे औषधि अधिनियम के अंतर्गत जारी किया जाता है । घरेलू उद्योग द्वारा दर्शाए गए आयात विशेष रूप से गैर-भेषज उद्योग के उपयोग हेतु किए गए हैं । यह सूचित किया गया है कि भेषज उद्योग से घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो सकती क्योंकि जांच अवधि के दौरान कोई आयात नहीं किए गए । यह एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण घरेलू उद्योग को स्पष्टतः कोई खतरा नहीं है क्योंकि जांच अवधि के बाद किए गए आयातों में संबद्ध वस्तुओं की कीमत डी पी सी ओ कीमत से अधिक थी । अन्य शब्दों में आयात एम पी पी ए द्वारा निर्धारित डी पी सी ओ कीमत से दोगुनी कीमत पर किए गए थे, इस प्रकार यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई अथवा क्षति का कोई खतरा नहीं था ।

(v) मामला चाहे जो भी हो, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की संस्तुति करते हैं, तो इसे डी पी सी ओ कीमत के स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिसे एन पी पी ए ने लागत तथा 22 % से 26 % के पर्याप्त लाभ पर विचार करते हुए निर्धारित किया है । इस संबंध में चीन एवं स्विटजरलैंड से विटामिन - ए पामिटेड से संबंधित जांच की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसमें डी पी सी ओ के स्तर पर शुल्क का निर्धारण

करने की संस्तुति की गई थी। प्रकटीकरण विवरण के पश्चात् यह कहा गया है कि वर्तमान मामले की जांच अवधि 1.04.2007 से 31.03.2008 है। संबंधित डी पी सी ओ अधिसूचना जो इस दौरान लागू थी वह दिनांक 27 जुलाई, 2007 को जारी की गई थी, जिसमें दिनांक 25 नवम्बर, 2008 तक इसका मूल्य 366 रुपये/किग्रा. निर्धारित किया गया था। तत्पश्चात् 25 नवम्बर, 2008 को डी पी सी ओ ने अधिसूचना जारी करके 544 रुपये/किग्रा. का मूल्य निर्धारित किया था। इस मामले के वास्तविक तथ्यों के दायरे में, चूंकि यह उत्पाद डी पी सी ओ के अंतर्गत आता है, अतः घरेलू उत्पादक इस उत्पाद की बिक्री निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर नहीं कर सकता बल्कि इससे कम कीमत पर कर सकते हैं। इस प्रकार जांच अवधि के दौरान दिनांक 25 नवम्बर, 2008 तक एम पी पी ए ने उसी कीमत पर विचार किया था जिस पर घरेलू उद्योग द्वारा इस उत्पाद की बिक्री की जा रही थी, जिसमें पर्याप्त लाभ पर भी विचार किया गया था। अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को इन्हीं कीमतों को जो उस दौरान लागू थी, घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत मानना चाहिए, यदि वे शुल्क को जारी रखने की संस्तुति करते हैं। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी एन पी पी ए के अधिकार को दरकिनार करके स्वतंत्र रूप से वह कीमत निर्धारित नहीं कर सकते जिस पर घरेलू उद्योग द्वारा इस उत्पाद की अधिकतम बिक्री की गई है। इसमें से किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने विवेकानुसार एन पी पी ए द्वारा दिनांक 25 नवम्बर, 2008 को जारी अधिसूचना के अनुसार डी पी सी ओ कीमतों पर विश्वास करते हैं, तो वह 544 रुपये/किग्रा. के स्तर से अधिक शुल्क की संस्तुति नहीं कर सकते हैं, जो लगभग 11.05 अम.डा./किग्रा. बनती है।

(vi) प्राधिकारी द्वारा भेषज उद्योग को इस आधार पर विशेष छूट दी जानी चाहिए कि चीन से ऐसे कोई आयात नहीं किए गए जिनका उपयोग भेषज उद्योग द्वारा किया गया हो, अतः घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(vii) यह उत्पाद औद्योगिक प्रयोक्ता द्वारा उत्पादित अंतिम उत्पाद फार्मूलेशन का हिस्सा है। पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने से अंतिम उत्पाद की लागत में वृद्धि होगी और आम आदमी के लिए स्वस्थ रहना कठिन हो जाएगा।

(viii) क्षति के संबंध में किया गया निवेदन घरेलू उद्योग द्वारा आवेदन में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर किया गया है। चूंकि क्षति विश्लेषण घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर किया गया है, अतः पी एच एल द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में बिन्दुवार विश्लेषण नहीं किया गया है।

च.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. पी एच एल तथा एंग्लो-फ्रेंच ड्राग्स एंड इंडस्ट्रीज लि०, बंगलौर ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि पंजीयन से संबंधित अपेक्षा के कारण भेषज उद्योग द्वारा आयात किया जाना संभव नहीं था। इस संबंध में यह नोट किया गया है कि संबद्ध वस्तुओं का प्रयोग भेषज तथा गैर-भेषज प्रयोजनों, दोनों के लिए किया जाता है अतः जांच अवधि अथवा उससे पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान यदि भेषज उद्योग द्वारा निर्यात नहीं किए गए तो इससे पाटन प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि

आयात पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद कभी भी किया जा सकता है। यह नोट किया गया है कि डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों में भेषज तथा गैर-भेषज उद्योग के उपयोगों में कोई अंतर नहीं किया गया है।

15. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि पाटनरोधी शुल्क संस्तुत किया जाता है तो इसका निर्धारण एन पी पी ए द्वारा निर्धारित डी पी सी ओ कीमतों के स्तर पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि एन आई पी का निर्धारण जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर किया जाता है जबकि एन पी पी ए प्राधिकारियों द्वारा विचार की गई अवधि भिन्न हो सकती है जिसमें वर्तमान जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति परलक्षित नहीं होगी। अतः डी पी सी ओ कीमत को पाटनरोधी शुल्क लागू करने का आधार (यदि यह संदर्भ कीमत हो) नहीं बनाया जा सकता। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क पाटित आयातों के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए लागू किया जाता है और यदि क्षति डी पी सी ओ कीमत जैसे किसी अन्य कारक द्वारा हुई, तो यह क्षति विश्लेषण का एक कारक बन जाता है कि क्या क्षति कम डी पी सी ओ कीमत के कारण हुई है। तथापि, किसी भी मामले में पाटनरोधी शुल्क पाटन की मार्जिन से अधिक नहीं होगा।

16. यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी इस उत्पाद की आयातक नहीं, बल्कि एक औद्योगिक प्रयोक्ता है। तथापि कंपनी ने अभी भी सूचना आयातक प्रश्नावली के प्रारूप में प्रस्तुत की है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि उनके द्वारा ऐसा किया जाना अधिदेशित नहीं है। आवेदक एक औद्योगिक प्रयोक्ता और नियम 6 (5) के अंतर्गत यथा परिभाषित हितबद्ध पक्षकार है और डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 11.2 के अंतर्गत प्रावधान है कि प्राधिकारी द्वारा जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ता को भी पाटन और क्षति, जो भी लागू हो, के बारे में जांच से सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, औद्योगिक प्रयोक्ता के लिए निर्दिष्ट अवधि के भीतर अधिदेशित सूचना प्रस्तुत करने हेतु कोई समयावधि निर्दिष्ट नहीं है। अतः कंपनी को कानून तथा पद्धति के अंतर्गत अपना निवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए जाने का अधिकार है, जिसका निर्वहन उसने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेकर और तत्पश्चात अपेक्षित तरीके से लिखित निवेदन प्रस्तुत करके किया है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों और इस उत्पाद के प्रयोक्ता को अपना उत्तर निर्धारित 40 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, पी एच एल ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया और निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत नहीं की। प्राधिकारी का अभिमत है कि यदि हितबद्ध पक्षकार एवं प्रयोक्ता निर्धारित अवधि के बाद सूचना प्रस्तुत करते हैं, तो यह कालातीत हो जाती है।

छ. पाटन मार्जिन की गणना की विधि

छ.1 घरेलू उद्योग के विचार

17. घरेलू उद्योग ने चीन के एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने का दावा किया है। उन्होंने नियमावली के अंतर्गत निर्धारित 15 अनिवार्य शर्तों के बारे में एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया है जिन्हें प्रत्येक इच्छुक निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने के लिए पूरा करना पड़ता है और ऐसे दावे को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित सूचना एवं साक्ष्य प्रस्तुत करना

पड़ता है। आवेदकों ने दावा किया है कि जब तक चीन के निर्यातक इन मानकों को पूरा नहीं करते, निर्दिष्ट प्राधिकारी से सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध - 1 के पैरा 7 के अनुसार करने की अपेक्षा की जाती है।

छ.2 निर्यातकों/आयातकों एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. सामान्य मूल्य के संबंध में किसी भी निर्यातक, आयातक, उपभोक्ता अथवा अन्य किसी हितबद्ध पक्षकार ने कोई टिप्पणी अथवा निवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. प्राधिकारी द्वारा चीन जन गण के निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली तथा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार से संबंधित प्रश्नावली की प्रतियां भिजवाई गई थीं, तथापि किसी भी निर्यातक ने जांच शुरुआत अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया और कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की। सूचना के अभाव में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (2) के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का खंडन नहीं किया गया। अतः प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण उपर्युक्त अनुबंध के पैरा 7 के अनुसार किया है। किसी भी सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य का निर्धारण "किसी अन्य उचित आधार" पर किया है।

छ.4 सामान्य मूल्य

20. इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य विटामिन - सी के विनिर्माण हेतु प्रमुख कच्चे माल की भारत में आयातित कीमतों, खपत मानदंडों एवं घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत तथा समुचित लाभ को ध्यान में रखकर संरचित किया है। उपर्युक्त के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर जांच अवधि के दौरान औसत विनिमय दर 1 अम डालर = 40.75 मानते हुए सामान्य मूल्य की गणना *** रुपये/किग्रा. अथवा *** अम.डॉ./किग्रा की गई है।

छ.5 निर्यात कीमत

21. निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु डी जी सी आई एंड एस द्वारा विचाराधीन उत्पाद से संबंधित आयातों के सभी सौदेवार आंकड़ों पर विचार किया गया है। इन सभी सौदों पर विचार करते हुए भारत औसत निर्यात कीमत (सी आई एफ) की गणना की गई है। निवल निर्यात कीमत की गणना करने के लिए अंतर्देशीय माल भाड़े, समुद्री माल भाड़े तथा पत्तन व्ययों का समायोजन किया गया है।

22. उपर्युक्त पद्धति के आधार पर, जांच अवधि के दौरान रही 1 अम.डॉ. = 40.75 रुपये की औसत विनिमय दर पर विचार करके *** रुपये/किग्रा. अथवा *** अम.डॉ./किग्रा. निर्यात कीमत का परिकलन किया गया है।

छ.6 पाटन मार्जिन

23. उपर्युक्तानुसार निर्धारित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत पर विचार करते हुए जांच अवधि के दौरान भारत के सूचित आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। पाटन मार्जिन का निर्धारण *** अम.डॉ./किग्रा. तथा 78.3% के रूप में किया गया है।

ज. क्षति निर्धारण की पद्धति तथा कारणात्मक संबंध की जाँच

ज.1 घरेलू उद्योग के विचार

24. घरेलू उद्योग ने क्षति एवं कारणात्मक संबंध के विषय में अनेक तर्क दिए हैं, जिनका सारांश निम्नानुसार है। कुछेक मुख्य तर्क हैं :-

- (क) घरेलू उद्योग, पाटित आयातों के कारण अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ था।
- (ख) पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है। जिसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में रूकावट आई है।
- (ग) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हो रहा था। परिणामस्वरूप, पाटनरोधी शुल्क हटा लिए जाने की स्थिति में, घरेलू उद्योग अपनी वर्तमान कीमतें प्रभारित नहीं कर सकेंगे। यह ऐसी स्थिति होगी जहां घरेलू उद्योग बिक्री कीमतों में उर्ध्वगामी वृद्धि (निविष्टि लागतों में वृद्धि के कारण) की अपेक्षा कर रहा है। अतः आयातों के कारण घरेलू उद्योग ऐसी परिस्थिति में अपनी कीमतों में कटौती करने के लिए बाध्य हो जाएगा जबकि घरेलू उद्योग कीमतों में उर्ध्वगामी वृद्धि की अपेक्षा कर रहा है।
- (घ) पाटनरोधी शुल्कों के समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में आयातों की संभावित मात्रा, उच्च होगी। अतः पाटनरोधी शुल्क के समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग की बिक्री (और उसके परिणामस्वरूप, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा उत्पादकता, में गिरावट आएगी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की वस्तुसूची के स्तर में वृद्धि होगी।
- (ङ) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में उत्पादन में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में बढ़ोत्तरी होगी। अतः पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने से लाभ और उसके परिणामस्वरूप निवेश पर आय एवं नकद प्रवाह का ह्रास होगा।
- (च) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में बिक्री कीमत में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में बढ़ोत्तरी होगी। अतः पाटनरोधी शुल्क वापस लिए जाने से लाभ और उसके परिणामस्वरूप निवेश पर आय एवं नकद प्रवाह का ह्रास होगा।
- (छ) बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह इत्यादि में संभावित गिरावट से घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक हो जाएगी।

ज.2 निर्यातकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं इत्यादि के विचार

25. निर्णायक समीक्षा के आरंभ होने के पश्चात किसी निर्यातक/आयातक द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है। तथापि, सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात, घरेलू उद्योग को हुई क्षति संबंधी टिप्पणियाँ मै0 पीरामल हेल्थकेयर लि0 को प्रस्तुत की गई थी। क्षति मानदण्डों के विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विवरण पर नहीं बल्कि घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों पर विश्वास किया है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. प्राधिकारी ने नोट किया है कि निर्णायक समीक्षा के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम धारा 9(क) (5) के संगत प्रावधान निम्नानुसार है :-

" इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क, यदि उसे पहले ही समाप्त न किया गया हो, लागू करने की तारीख से पाँच वर्षों के समाप्त होने के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा;

बशर्ते कि यदि केन्द्र सरकार का मत किसी समीक्षा में, यह हा कि ऐसे शुल्क के समापन से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उनकी पुनरावृत्ति की संभावना है, तो वह, समय-समय पर ऐसे शुल्कों को आगे और पांच वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकती है और यह बढ़ाई गई अवधि ऐसे विस्तार की तारीख से आरंभ होगी।

27. पाटनरोधी नियम के नियम 23 में निर्णायक समीक्षा करने की क्रियाविधि दी गई है। समीक्षा करने के लिए नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 एवं 20 के प्रावधानों को अपनाया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम के अनुसार, निर्णायक समीक्षा में क्षति की वर्तमान स्थिति का आकलन किया जाना है।

28. इस संबंध में डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 तथा पाटनरोधी नियम के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद हेतु घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; तथा (ख) पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव हेतु एक विषयपरक जांच का प्रावधान किया गया है। प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या भारत में समग्र अर्थों में या उत्पादन अथवा खपत की तुलना में आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या आयातक देश में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का उद्देश्य अन्यथा मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती।

29. क्षति की वर्तमान स्थिति के आकलन के प्रयोजनार्थ, नियम के अनुबंध-II में क्षति के निर्धारण हेतु ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुगत जांच को शामिल किया जाना अपेक्षित है। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमों में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक एवं संभावित गिरावट, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग, घरेलू कीमत को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन के मार्जिन की मात्रा; नकद प्रभाव पर वास्तविक एवं संभावित नकारात्मक प्रभाव, वस्तुसूचियां, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश करने की क्षमता सहित, उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों तथा संकेतकों का विषयपरक तथा निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच निम्नानुसार की गई है :-

30. क्षति की वर्तमान स्थिति के आकलन के प्रयोजनार्थ पाटन एवं क्षति के बीच क्षति एवं कारणात्मक संबंधों की मौजूदगी यदि कोई हो, की जांच करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की मात्रा एवं कीमत प्रभाव और कीमत एवं लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है।

(क) मात्रा प्रभाव:- संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है:-

(i) मांग का मूल्यांकन

31. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू खपत/मांग का परिकलन करने के लिए प्राधिकारी ने भारत में हुए कुल आयातों को घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा के साथ जोड़ा है।

ईकाई मी.टन में	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जांच अवधि)
घरेलू उद्योग की बिक्री	316	405	665	837
कुल आयात	301	239	526	295
मांग	617	644	1191	1132

प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान मांग में सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित हुई है एवं उसमें वृद्धि हुई है। आधार वर्ष (2004-05) से जांच अवधि में यह बढ़कर 83% हो गया।

(ii) आयात मात्राएं एवं बाजार हिस्सा

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जांच अवधि)
आयात (मी.टन)				
चीन से	46	41	106	103
अन्य देश	255	198	420	192
कुल आयात	301	239	526	295
आयातों में बाजार हिस्सा (%)				
चीन	15	17	20	35
अन्य देश	85	83	80	65
मांग (मी.टन)	617	644	1191	1132
मांग में बाजार हिस्सा (%)				
चीन	7.45	6.37	8.90	9.10
अन्य देश	41.33	30.74	35.26	16.96
घरेलू देश	51.22	62.89	55.84	73.94

32. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश से सभी आयातों को पाटित आयात माना गया है। आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि:-

(क) वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 के बीच पाटित आयातों की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। वर्ष 2007-08 में मात्रा में गिरावट आई थी तथापि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान मात्रा में वृद्धि हुई है।

(ख) कुल आयातों में संबद्ध देश के हिस्से में क्षति अवधि के दौरान अत्यधिक वृद्धि हुई थी।

(ग) संबद्ध देश के संबंध में मांग में बाजार हिस्सा जो वर्ष 2004-05 के दौरान केवल 7.45% था, वह जांच अवधि के दौरान बढ़कर 9.10% हो गया।

(iii) उत्पादन, बिक्री, क्षमता एवं क्षमता उपयोग

33. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री क्षमता एवं क्षमता उपयोग निम्नानुसार था:-

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
क्षमता	मी.टन	600	720	1,170	1,440
प्रवृत्ति		100	120	195	240
उत्पादन	मी.टन	507	571	841	1,009
प्रवृत्ति		100	113	166	199

क्षमता उपयोग	%	84.44	79.24	71.91	70.05
अप्रत्युक्त क्षमता	मी. टन	93	149	329	431
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	316	405	665	837
प्रवृत्ति		100	128	210	265

34. घरेलू उद्योग की क्षमता आधार वर्ष में 600 मी. टन से बढ़कर जाँच अवधि में 1440 मी. टन हो गई। उसी अवधि के दौरान उत्पादन 507 मी. टन से बढ़कर 1009 मी. टन हो गया। इसी प्रकार, उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री भी 316 मी. टन से बढ़कर, 837 मी. टन हो गई। क्षमता उपयोग 84% से घटकर 70% रह गया परंतु यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता वर्ष 2006-07 में मै0 बजाज हेल्थकेयर के प्रवेश के कारण बढ़ी थी। आगे यह नोट किया गया है कि जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता मौजूद थी।

(iv) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

35. कीमत कटौती एवं कम कीमत पर बिक्री, यदि कोई हो, के संबंध में संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण पर घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जाँच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) तथा क्षति रहित कीमत (एनआईपी) (घरेलू उद्योग की लागत संबंधी सूचना के आधार पर निर्धारित) की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य से की गई है।

(क) कीमत कटौती

36. पाटित आयातों द्वारा की जा रही कीमत कटौती का पता लगाने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की पहुँच कीमत के साथ की है। निवल बिक्री प्राप्ति समस्त छूटों और करों को घटाने के बाद निकाली गई थी। आयातों के पहुँच मूल्य की गणना संबद्ध आयातों के सीआईएफ मूल्य में 1% हैंडलिंग प्रभार लागू मूल सीमाशुल्क जोड़कर की गई है। आयातों के पहुँच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ की गई है और यह पाया गया है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
चीन से सीआईएफ निर्यात कीमत रु./कि.ग्रा.	207	207	169	290
चीन से आयातों का पहुँच मूल्य रु./कि.ग्रा.	261	251	196	322
निवल बिक्री प्राप्ति (रु./कि.ग्रा.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	81	90	115
बिक्री लागत (रु./कि.ग्रा.)	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	86	95	140
कीमत कटौती रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती की रेंज %	***	***	***	***

37. यह नोट किया जाता है कि पाटित आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है। समूची क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती 15-40% के बीच रही थी। जाँच अवधि के लिए कीमत कटौती 20-30% के बीच रही थी।

ख. कम कीमत पर बिक्री

निवल बिक्री प्राप्ति (रू./कि.ग्रा.)	***
क्षति रहित कीमत (रू./कि.ग्रा.)	***
कम कीमत पर बिक्री (चीन जन. गण.)	***
कम कीमत पर बिक्री (%)	***
कम कीमत पर बिक्री की रेंज	10-15

38. कम कीमत पर बिक्री क्षति के निर्धारण का एक प्रमुख संकेतक है; इसलिए प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत निकाली है और उसकी तुलना कम कीमत पर बिक्री की मात्रा की गणना के लिए पाटित आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की है। घरेलू उत्पादक के लिए क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन लागत पर उचित विचार करने के बाद किया गया है। विश्लेषण से यह पता चलता है कि चीन जन. गण. से कम कीमत पर बिक्री 10-15% के बीच रही है।

(v) क्षति के अन्य मापदंडों की जांच

39. घरेलू उद्योग की मात्रा और कीमत पर पाटित आयातों के प्रभाव और आयातों की मात्रा एवं मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री के साथ-साथ पूर्ववर्ती खंड में विभिन्न क्षेत्रों के बाजार हिस्से के साथ खपत की पद्धति की जांच करने के बाद ऐसे अन्य आर्थिक मापदंडों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी का पता चल सकता है।

(क) लाभ एवं नकद प्रवाह पर वास्तविक तथा संभावित प्रभाव

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जांच अवधि)
बिक्री लागत (रू./कि.ग्रा.)	रू./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	95	140
निवल बिक्री प्राप्ति (रू./कि.ग्रा.)	रू./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	81	90	115
लाभ/(हानि) प्रति इकाई	रू./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	(139)	(165)	(1027)
लाभ/(हानि) (पीबीटी)	रू./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	(178)	(347)	(2721)
लाभ/(हानि) पीबीआईटी	रू./लाख	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	(37)	22	(901)
नकद लाभ	रू./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति		100	42	118	(329)

40. आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत में 40% (141 रू./कि.ग्रा.) की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान निवल बिक्री प्राप्ति में 15% (54 रू./कि.ग्रा.) की वृद्धि हुई। प्रति इकाई लाभ जो आधार वर्ष में सकारात्मक था, ऋणात्मक था और यह आधार वर्ष के 100 की तुलना में जांच अवधि में -80 (सूचीबद्ध) रहा था। जांच अवधि में लाभ (पीबीआईटी) भी इसी प्रकार ऋणात्मक रहा। आधार वर्ष के 100 की तुलना में जांच अवधि में यह -901 (सूचीबद्ध) रहा था।

41. नकद प्रवाह की प्रवृत्ति के बावजूद घरेलू उद्योग के नकद लाभ का निर्धारण किया गया है और प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि जांच अवधि में यह ऋणात्मक हो गया है। आधार वर्ष के 100 की तुलना में जांच अवधि में यह -329 रहा था।

(ख) रोजगार, मजदूरी एवं उत्पादकता

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
कर्मचारियों की सं.	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	109	111	114
मजदूरी	रु./लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	131	249	474
उत्पादन की प्रति इकाई मजदूरी	रु./मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	116	150	238
उत्पादकता	मी. टन/दिन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	166	199

42. दोनों कंपनियाँ बहु-उत्पाद कंपनियाँ हैं। बजार हेल्थ केयर लि. ने केवल वर्ष 2006-07 में उत्पादन शुरू किया है। आधार वर्ष की तुलना में कर्मचारियों की सं. में जांच अवधि में 14% की वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मजदूरी में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ग) मालसूची

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
औसत स्टॉक	मी. टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	मी. टन	100	88	414	521

43. घरेलू उद्योग के पास तैयार उत्पादों के औसत स्टॉक में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई। बिक्री दिवसों के संबंध में यह आधार वर्ष में 1.29 दिन से बढ़कर जांच अवधि में 2.35 दिन हो गई।

(घ) निवेश पर आय तथा पूंजी जुटाने की क्षमता

विवरण	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
निवल नियत परिसम्पत्तियाँ	लाख रु.	***	***	***	***
कार्यशील पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
लगाई गई पूंजी- एनएफए आधार पर (कुल)	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	238	248
लगाई गई पूंजी पर आय (घरेलू)	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	(147)	(146)	(1095)

44. आंकड़ों से यह पता चलता है कि आधार वर्ष की तुलना में लगाई गई पूंजी में, जांच अवधि में 148% की वृद्धि हुई। लगाई गई पूंजी में यह वृद्धि निवल नियत परिसम्पत्ति एवं कार्यशील पूंजी में बढ़ोत्तरी के कारण हुई थी। लगाई गई पूंजी पर आय जो आधार वर्ष में सकारात्मक थी, वर्ष 2005-06 में ऋणात्मक हो गई और उसके बाद यही प्रवृत्ति जारी रही।

(ड.) वृद्धि

45. क्षति के अनेक मापदंडों से क्षति अवधि के दौरान प्रतिकूल प्रभाव का पता चलता है।

(च) पाटन मार्जिन की मात्रा

46. प्राधिकारी ने चीन से हुए आयातों के मामले में अत्यधिक सकारात्मक पाटन मार्जिन पाया है। चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी भारतीय बाजार में अपनी सामग्री का पाटन करना जारी रखा। वस्तुतः पाटन का मार्जिन अभी भी काफी अधिक है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है।

(झ) कारणात्मक संबंध

47. क्षति अवधि अर्थात् वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान संबद्ध वस्तु की माँग में वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में इसमें 83% की वृद्धि हुई है।

48. घरेलू उद्योग ने वर्ष 2005-06, 2006-07 और जांच अवधि में क्षमता में वृद्धि की है और यह 600 मी. टन से बढ़कर 1440 मी. टन हो गयी है। इसी अवधि में उत्पादन दोगुना हो गया है। बिक्री भी 316 मी. टन से बढ़कर 837 मी. टन हो गयी है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा मौजूदा 51% से बढ़कर 74% हो गया जिससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने बाजार में बढ़ती हुई माँग का लाभ उठाया है।

49. प्राधिकारी ने नोट किया है कि उत्पादकों का कार्यक्षेत्र पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद बदल गया है जो उत्पादक मूल जांच अवधि में घरेलू उद्योग थे, वे अस्तित्व में नहीं रह सके और उन्होंने बाजार छोड़ दिया। पूर्व में अम्बा लाला साराभाई उत्पादक था लेकिन वह अब उत्पादन नहीं करता है। इस संदर्भ में यह नोट किया गया है कि पूर्व में बाजार हैल्थ केयर लि. एक व्यापारी था लेकिन अब वह संबद्ध वस्तु का उत्पादक बन गया है। इस प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि संबद्ध वस्तु के उत्पादक व्यापार को जारी रखने में भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

50. क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत में 40% (141 रु./कि.ग्रा.) की वृद्धि हुई जबकि बिक्री कीमत में 15% (54 रु./कि.ग्रा.) की बिक्री हुई। वर्ष 2004-05 में लाभ की स्थिति थी जो वर्ष 2005-06 में प्रति इकाई घाटे के रूप में तब्दील हो गयी। वर्ष 2006-07 और 2007-08 में स्थिति और खराब हो गयी। लगाई गई पूंजी पर आय वर्ष 2004-05 में 100 (सूचीबद्ध) से घटकर -1095 (सूचीबद्ध) हो गयी।

51. घरेलू उद्योग को लगातार हो रही हानि से यह पता चलता है कि बाजार हिस्से में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी रही है।

ऐसे अन्य कारक जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है

52. प्राधिकारी ने पाटित आयातों से इतर निम्नलिखित ज्ञात कारकों की भी जांच की है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है या क्षति में योगदान मिल सकता है।

(क) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा तथा कीमतें

अन्य देशों से आयातों की मात्रा भी बहुत अधिक है हालांकि इन देशों से निर्यात कीमतें संबद्ध देश की निर्यात कीमत से कहीं अधिक थीं।

(ख) खपत के पैटर्न में परिवर्तन:- विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

(ग) व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियाँ तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा :- ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति मौजूद नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा सके।

(घ) निर्यात निष्पादन:- आवेदकों ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। आवेदक के निर्यातों में वृद्धि हुई है। केवल घरेलू बिक्रियों के लिए ही घरेलू उद्योग की क्षति का विश्लेषण किया गया है। अतः घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला कारक नहीं माना जा सकता।

(ङ.) उत्पादकता:- घरेलू उद्योग की उत्पादकता में कमी आई है। तथापि उत्पादकता में इस कमी का कारण बजाज हेल्थकेयर, जिसने नई सुविधाओं की स्थापना की है, द्वारा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना है। किसी भी स्थिति में, यदि इस उत्पादकता के प्रभाव को अलग कर भी दिया जाए तो यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

ट. क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग का अनुरोध

53. क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं :-

(क) विचाराधीन उत्पाद का पाटन जारी रहने की संभावना है। यह निम्नलिखित से सिद्ध हो जाता है (क) पहले ही चीन से अत्यधिक निर्यात किया जा रहा है; (ख) चीनी सीमाशुल्क विभाग तथा भारतीय सीमाशुल्क विभाग द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात मात्रा में अत्यधिक अंतर है जो संभावित अपवंचन तथा शुल्क रद्द किए जाने की स्थिति में और अधिक पाटन की संभावना को सिद्ध करता है; (ग) चीन से तुलनीय कीमतों (या उससे भी कम) पर वैश्विक निर्यात।

(ख) वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि (क) पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहेगा; (ख) मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटन की मात्रा भी बढ़ जाएगी।

(ग) याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि पाटन मार्जिन का मौजूदा स्तर 75% है जो न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि बहुत अधिक भी है। पूर्व जाँचों के समय की परिस्थितियाँ मौजूदा जाँच अवधि में भी पूर्णतया विद्यमान हैं।

- (घ) आगे याचिकाकर्ताओं का मत है कि इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि उपाय निरस्त किए जाने पर पाटन समाप्त हो जाएगा अथवा उसमें कमी आएगी ।
- (ड.) ऐसे कुछेक तर्क नीचे दिए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने अथवा अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ाए न जाने की स्थिति में पाटन का स्तर बढ़ जाएगा ।

(i) अन्य देशों को निर्यात

54. चीनी निर्यातक अनेक देशों को पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं । यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में देश में चीनी सामान का पाटन बढ़ जाएगा ।

55. याचिकाकर्ताओं ने चीन से विभिन्न देशों को किए जाने वाले निर्यातों का विश्लेषण किया और यह पाया गया कि भारत के लिए 296/-रुपए प्रति किग्रा. की तुलना में 226 रुपए प्रति किग्रा. की औसत कीमत पर चीन से 40,000 मी. टन विटामिन-सी का निर्यात किया गया था । वास्तव में केवल यूएस को ही लगभग 24,000 मी. टन का निर्यात 222 रुपए प्रति किग्रा. की कीमत पर किया गया है । अतः यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीनी उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार में बेहतर व्यापार अवसर पैदा होंगे । 1400 मी. टन की कम माँग को देखते हुए चीनी उत्पादक वास्तव में भारत की पूरी माँग को आसानी से पूरा कर सकते हैं ।

(ii) चीनी उत्पादकों की बेशी क्षमता

56. चीन में उत्पादकों द्वारा सृजित अत्यधिक क्षमता इस बात का संकेत है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारत में आयातों की मात्रा उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी । याचिकाकर्ता चीन में संबद्ध वस्तु के कुछेक उत्पादकों से संबंधित सूचना जुटाने में सफल रहे हैं जिससे निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होती है:-

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	क्षमता/उत्पादन (मी. टन)
1	नॉर्दन जनरल फार्मास्यूटिकल्स फैक्टरी	22,000
2	जियांगसू जियांगसन फार्मास्यूटिकल्स कं०	20,000
3	हेबेई वेलकम फार्मास्यूटिकल्स	20,000
4	वेइशांग फार्मास्यूटिकल्स (शिजियाजुआंग)	25,000
5	जिबो हुआलांग फार्मास्यूटिकल्स	5,000
	कुल	92,000

57. प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियाँ प्राप्त करने के बाद पाटन तथा क्षति की संभावना से संबंधित विश्लेषण निष्पादित करेंगे ।

ठ. कारणात्मक संबंध, पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

58. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है जैसाकि इन परिणामों के पिछले हिस्से में पाटन मार्जिन के विश्लेषण से स्पष्ट है । घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. में उत्पादकों के नाम तथा उनकी क्षमताओं की सूचना दी है । तथापि किसी साक्ष्य के अभाव में घरेलू उद्योग की सूचनाओं को तथ्य नहीं

माना जा सकता है। लेकिन यह भी नोट किया गया है कि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने सहयोग नहीं किया है और न ही चीन जन.गण. में उपलब्ध बेशी क्षमताओं के संबंध में कोई सूचना/साक्ष्य प्रस्तुत किया है। प्राधिकारी इस तथ्य को भी नोट करते हैं कि यूएसए में विटामिन-सी से संबंधित विश्वास भंग करने संबंधी मुकदमे में मॉफ्कोम न्यायालय में हाजिर हुआ था और उसने यह सूचित किया था कि चीन जन.गण. में विटामिन-सी के उत्पादकों द्वारा दी गई कीमतें मॉफ्कोम द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा यह भी नोट किया गया है कि यूएसए में विटामिन-सी के क्रेता द्वारा विश्वास भंग करने संबंधी मुकदमा तब दायर किया गया था जब चीनी विनिर्माताओं ने कीमतें तय करने और यूएस को विटामिन-सी के निर्यात को सीमित करने के लिए एक उत्पादक संघ गठित किया था। इस तथ्य के मद्देनजर कि संबद्ध देश से पाटन जारी है और रिकॉर्ड में इस बात से संबंधित किसी सामग्री के अभाव में कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन रूक जाएगा, प्राधिकारी का विचार है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहेगा।

59. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति जारी है। आगे प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में उत्पादक विटामिन-सी की बिक्री औषधि कीमत नियंत्रण आदेश के तहत करने के लिए बाध्य हैं अर्थात् वे एनपीपीए द्वारा तय की गई कीमत से अधिक कीमत पर अपना उत्पाद नहीं बेच सकते हैं। घरेलू उद्योग द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्होंने उत्पादन की बढ़ती लागत के मद्देनजर कीमतों में संशोधन करने के लिए एनपीपीए को आवेदन भेज दिया है।

60. चीन जन.गण. से ऐसी कीमतों, जिनसे घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री कीमतों में कटौती हुई, पर आयातों के जारी रहने से यह संकेत मिलता है कि शुल्क समाप्त किए जाने पर घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें चीन जन.गण. से आयात की कीमतों के समान रखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जिसके कारण घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन में और अधिक कमी आएगी। इसलिए प्राधिकारी का मत है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति बढ़ जाएगी।

ड. अंतिम परिणाम

61. उपर्युक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि:-

(क) चीन जन. के मूल क़ी अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु अपने सामान्य मूल्य से कम पर भारत को निर्यात की गई है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

(ख) संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क के जारी रहने के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार नहीं हुआ है;

(ग) और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी।

घ. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

62. सामान्यतः पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त कर भारतीय बाजार में खुली एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का परिवेश तैयार करना है जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी उपाय लागू करने से किसी भी रूप में संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होगा और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ण. सिफारिशें

63. संबद्ध देश से आयातों के कारण पाटन तथा क्षति का संभावना की निश्चितता का निर्धारण होने के मद्देनजर प्राधिकारी का यह विचार है कि संबद्ध देश से आयातों के विरुद्ध उपाय जारी रखने की आवश्यकता है। हालांकि संबद्ध देश से पाटन के वर्तमान स्तर और घरेलू उद्योग के निगदन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का मत है कि लागू उपायों में संशोधन आवश्यक है। अतः प्राधिकारी नीचे उल्लिखित रूप में व तरीके से संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने को आवश्यक मानते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क संदर्भ कीमत के रूप में है। तथापि वह उत्पादन लागत में परिवर्तनों और कीमतों में वृद्धि होने के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने से रोकने में सफल नहीं रहा है। यह स्थिति जारी रहने नहीं दी जा सकती क्योंकि पाटनरोधी उपाय अल्पावधि के लिए होते हैं ताकि घरेलू उद्योग संबद्ध देश से आयातों के कारण खड़ी हुई चुनौतियों का सामना कर सके। यदि शुल्क का प्रकार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की समुचित भरपाई करने में सक्षम नहीं है तो उसे बदला जाना आवश्यक है। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी शुल्क को पूर्व निर्धारित शुल्क के रूप में रखा जाए क्योंकि कच्चे माल (2-केजीए) की कीमतों में वृद्धि के कारण संदर्भ कीमत के रूप में शुल्क निरर्थक होगा। अतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के अनुरोध को मान लिया है और वे पूर्व निर्धारित शुल्क के रूप में शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं।

65. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क संबंधी नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटन मार्जिन अथवा क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं। अतः प्राधिकारी इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर नीचे दी गई तालिका के कॉलम-9 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं।

क्र. सं.	टैरिफ मदें	वस्तु का विवरण	ग्रेड	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2936.27	विटामिन-सी *	कोई	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	3.99	किग्रा.	अम.डॉ.
2	वही	वही	वही	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. के अतिरिक्त कोई अन्य देश	कोई	कोई	3.99	किग्रा.	अम.डॉ.
3	वही	वही	वही	कोई	चीन जन.गण.	कोई	कोई	3.99	किग्रा.	अम.डॉ.

* यह पाटनरोधी शुल्क विटामिन-सी के सभी समानार्थकों पर लागू है। तथापि विटामिन-सी के सर्वाधिक सामान्य समानार्थक एस्कॉर्बिक एसिड, एल-जाइलोएस्कॉर्बिक एसिड, 3-ऑक्सो-एल-ग्युलोफ्यूरैनोलेक्टोन (एनोल प्रकार), एल-3, केटोथिओहेक्स्यूरॉनिक एसिड लेक्टॉन, आदि हैं जैसाकि मर्क सूची की प्रविष्टि संख्या '867 के तहत उल्लिखित है।

66. केन्द्र सरकार द्वारा इस आदेश को स्वीकृति मिलने के बाद इसके विरुद्ध कोई भी अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2009

FINAL FINDINGS

(Sunset Review)

Subject : Anti-dumping investigation (Sunset Review) involving import of Vitamin-C originating in or exported from China PR.

No. 15/16/2008-DGAD.—

A Background of the Case

Whereas The Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of Vitamin-C (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR (referred to as subject country) falling under Sub-heading 293627. The Designated Authority came out with final findings in the matter of first Sunset Review on 31.07.2003 vide notification no 14/14/2002-DGAD and definitive anti dumping duty was imposed by Ministry of Finance as per Customs notification No159/2003 dated 24th October 2003.

2. The Designated Authority, in pursuance of the judgment of the Hon'ble Delhi High Court in WC No.16893 of 2006 initiated on 23rd May 2008 the sunset review of anti-dumping duty imposed on imports of Vitamin-C originating in or exported from China PR in accordance with section 9A(5) of the Customs Tariff Act and Rule 23 of the Rules to review the need for continued imposition of duties, in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The domestic industry submitted information seeking continuation of anti dumping duty on the ground that domestic industry is suffering current injury from the continuous dumped imported from the China PR and revocation of the duty would lead to intensified injury to the domestic industry. The information was provided by M/s Amoli Organics Pvt Ltd. and M/s. Bajaj Health Care Ltd on behalf of the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

- I. After initiation of the review investigation, the Authority notified the domestic industry and called for the information within 40 days of the issue of the notification. On receipt of the information from the domestic industry, other interested parties were provided opportunity to submit information in the prescribed formats within 40 days of the letters issued to them.
- II. All known exporters/producers in the subject country were informed to submit information within 40 days of issue of the letters on prescribed proforma (questionnaire responses) and necessary information in accordance with Rule 6(4);
- III. None of the exporters responded to the questionnaire in response to the above notification in the permitted time. Therefore, they have been treated as non-cooperating exporters.
- IV. The Embassy of the subject country in New Delhi was also informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.
- V. A copy of initiation notification along with the importers questionnaire was also sent to the known importers and users of the subject goods in India calling for necessary information within 40 days of issue of the letters in accordance with Rule 6(4).
- VI. In response to the above notification, none of the importers or users has filed response to the questionnaire in the permitted time. Therefore, they have been treated as non-cooperating importers/users.
- VII. The following domestic producers of the subject goods have provided their cost and injury information for investigation:-

M/s Amoli Organics Pvt Ltd
M/s Bajaj Health Care Ltd
- VIII. The Authority kept available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties in accordance with Rule 6 (7).
- IX. The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible to examine the injury suffered and to work out optimum cost of

production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.

- X. In accordance with Rule 6(6), the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 3rd February 2009. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally.
- XI. The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.
- XII. In accordance with Rule 16 of the anti-dumping Rules, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to the known interested parties and comments received on the same have been dealt with in the final findings.
- XIII. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available in accordance with Rule 6(8).
- XIV. The period of investigation for the purpose of the present review is 1st April 2007 to 31st March 2008 (12 months). However, injury analysis covered the years 2004-2005, 2005-2006, 2006-07 and POI.
- XV. **** In the statement represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE:

C.1 VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

- 4. Domestic industry has submitted with regard to product under consideration and like article:
 - (i) Present investigation is a review investigation, product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation. There has been no significant development in the product over the period.
 - (ii) The goods produced by the domestic industry are like article to the imported product.

C.2 Views of the importers, consumers, exporters and other interested parties

5. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to product under consideration and like articles.

C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY

6. The product under consideration in the present investigation is Vitamin-C. The most commonly used synonyms of vitamin C are ascorbic Acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-Oxo-L-gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone, etc., as described under entry number "867 of MERCK INDEX". The product is classified under Customs Tariff heading 2936.27 and at subheading 29362700 as per Indian Trade Classification. The Customs and ITC HS classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. The Product has uses in pharmaceutical and non- pharmaceutical industry. This being a Sunset Review, therefore, there is no change in scope of the product under consideration.

7. There is no significant difference in Vitamin-C produced by the Indian industry and Vitamin-C exported from China PR, which can have an impact on price. Vitamin-C produced by the Indian industry and imported from subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Therefore, Vitamin-C produced by the domestic industry and imported from China PR are being treated as like article in accordance with the anti dumping Rules.

D. Domestic Industry

8. The present application has been filed by M/s Amoli Organics Pvt Ltd., Mumbai and M/s. Bajaj Health Care Limited, Mumbai. It has been noted that earlier M/s Ambalal Sarabhai was applicant in the original investigation. However, this company has not responded to the present Sunset Review. As per the information provided by the applicants, M/s Amoli Organics Pvt Ltd., Mumbai and M/s. Bajaj Health Care Limited, Mumbai are the only producers of this product. As the applicants account for 100% of the Indian production, therefore, they constitute the domestic industry within Rule 2(b).

E. Confidentiality

9. The information provided by the domestic industry concerning mainly relating to customers, cost and finance have been kept confidential. However, the information concerning volume of sale, production, capacity etc. of domestic industry as a whole has not been treated confidential.

F. Other Issues**F.1 Issues raised by interested parties during the public hearing and after Disclosure Statement**

10. After initiation of the Sunset Review, none of the exporter, importer or other interested parties responded to the initiation and provided any information. However, during the public hearing, number of the interested parties including importers came to attend the hearing. Subsequently, M/s Piramal Healthcare Limited (PHL) claiming to be importer and industrial user submitted its response on February 10, 2009 on importers questionnaire response. From the information provided, it has been noted that no information about imports made have been provide in their submissions.

11. A submission was made on behalf of M/s North East General Pharmaceutical Company Limited, China by Shri M.N. Jha, Advocate on 10.2.2009. A photocopy of the authorization dated 3.2.2009 in favour of Shri M.N. Jha was also enclosed. In the submission, some comments have been made concerning injury to the domestic industry. As original letter of authorization was not filed, therefore, the submission have not been taken on record. After disclosure statement, it has been stated by the company that non-submission of original authorization letter is a flimsy ground for rejecting their valid submission through a dignified Advocate. The Advocate was available to the Authority for clarification and was never asked for original copy of the authorization letter. In this regard, the Authority notes that Advocate can make submission only on behalf of their client, any submission without valid authorization cannot be considered valid. The Authority has, however, made correction in the data as pointed out in the comments by the company.

12. The Authority notes that PHL has not provided information within the stipulated time, the same could not be considered as cooperating importer. However, the legal or other factual issue raised have been dealt with in the appropriate section of this findings.

13. M/s Piramal Healthcare Limited have made the following submissions:-

- (i) The product is governed under National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA). During the period of investigation, the NPAA vide its Notification No. 1280(E) dated 27.7.2007 the pricing for the product was fixed as Rs.366/kg..
- (ii) Imports of the product for the purpose of usage in pharmaceutical industry is governed under Central Drugs Standard Control Organization (Registration Certificate Form 41). Without specific permission to foreign manufacturer product cannot be imported and used by pharmaceutical industry. This exclusive permission was only granted to an exporter, i.e. M/s North East General Pharmaceutical Co. Ltd. in China for the first time, producing the said product with effect from 1st October 2008. Prior to this, the pharmaceutical industry was sourcing the subject product for the purposes of usage in the final product either locally or from Japan and Europe.

- (iii) PHL received the permission (Form 9 & Form 10 under the Drug Act) in the month of November 2008. The imports were made by PHL only in December 2008 which was clearly outside the period of investigation.
- (iv) Uses of Vitamin C by pharmaceutical industry is strictly governed by an import licence to be issued under Drugs Act. The imports shown by the domestic industry from China is specifically imported for use of non-pharmaceutical industry. It has been stated that there cannot be injury to the domestic industry from pharmaceutical industry as no imports were made during the period of investigation. This being a Sunset Review, there is clearly no threat to the domestic industry for the reasons that the imports made post period of investigation, the price of subject goods are well above the DPCO price. In other words, the imports have been made at double the price of the DPCO fixed price by NPPA, thus showing that there is no material injury or any threat to the domestic industry.
- (v) In any case, if the Designated Authority recommends continuing the anti dumping duty on subject goods, the same should be fixed at the level of DPCO pricing fixed by NPPA taking into consideration the cost as well as the adequate profit of 22% to 26%. In this regard attention has been drawn to the investigation on Vitamin A palmitate from China and Switzerland wherein the duty was recommended to be fixed at the level of DPCO. After the disclosure statement, it has been stated that the period of investigation in the instant is 1.04.2007 to 31.3.2008. The relevant DPCO notification existed during this period dated July 27, 2007 until November 25, 2008 was fixed to be at Rs.366/per kg. Thereafter, the DPCO notification was issued on November 25, 2008 to fix the prices at Rs.544/per kg. While in the factual matrix of the case, since the products falls under the DPCO, the domestic producer cannot sell the product beyond the fixed price but can sell below the same. Thus, during the period of investigation until November 25, 2008, the NPPA had rightly considered the price at which the domestic industry is selling the product taking into consideration as well as adequate profit into account. Therefore, the Designated Authority should consider the same prices as it existed during that period to be the Fair Selling Prices of the domestic industry in case it recommends continuing duties. Further, the Designated Authority cannot overrule the power of NPPA to independently fix the prices at which the domestic industry should at maximum sell the product. Without prejudice to the same, in case the Designated Authority in its wisdom even relies upon the DPCO prices as fixed by the NPPA in its notification dated November 25, 2008, the Designated Authority cannot recommend the duties beyond the level of Rs.544/kg, which roughly translates into USD 11.05/per kg.
- (vi) The Authority should grant special exemption to the pharmaceutical industry on the basis that there have been no imports from China which have been used by the pharmaceutical industry, thus there is no question of any alleged injury to the domestic industry.
- (vii) The product form part of final product formulation produced by the industrial user. The imposition of anti dumping duty would only result in increasing the cost of final product, thus making it difficult for the common men in keeping the good health.

- (viii) Submissions have been made concerning injury based on the fact submitted by the domestic industry in the application. As the injury analysis has been carried out on the basis of verified data of the domestic industry, therefore, point-wise analysis has not been done on the objections raised by PHL.

F.2 Examination by the Authority

14. It has been contended by PHL and Anglo French Drugs & Industries Limited, Bangalore that imports by the pharmaceutical industry could not be possible because of the registration requirement. In this regard, it has been noted that the subject goods has both pharmaceutical and non-pharmaceutical uses, therefore, if the imports were not made by the pharmaceutical industry during the POI or preceding years, it would not affect the dumping proceeding as imports can be made at any time after completion of the registration proceeding. It has been noted that in the DGCI&S imports data, no differentiation has been made about the uses in the pharmaceutical and non-pharmaceutical industry.

15. It has also been contended that in case anti-dumping duty is to be recommended, it should be fixed at the level of DPCO prices fixed by NPPA. In this regard, the Authority notes that the NIP is determined by taking into cost of production of the domestic industry during POI whereas the period taken into consideration by NPPA authority may be different which may not reflect the actual injury to the domestic industry during the current POI. Therefore, DPCO price cannot be treated as basis for imposing the anti-dumping duty (in case it is a reference price). The Authority also notes that the anti-dumping duty is imposed to neutralize the effect of dumped imports, in case injury is contributed by any other factor such as DPCO price, it becomes factor to be analyzed for injury to understand whether injury has been caused by lower DPCO price, however, the anti-dumping duty in no case shall exceed the margin of dumping.

16. It has been contended that the company is not an importer but an industrial user of the product. However, the company choose to provide information under the format of Importers' questionnaire in spite of the fact that they were not mandated to do so. The applicant is an industrial user and defined as an interested party as defined under the Rules. Rule 6(5) and also Article 11.2 of the WTO Agreement mandate that Authority shall also provide opportunity to industrial user of the article under investigation to furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping and injury wherever applicable. Further, there is no time line specified for industrial user to provide mandated information within the specified period. Therefore, the company has right under the law and practice to be given an opportunity to make its submissions which it clearly did so by attending the public hearing and thereafter filing written submissions as required to do so. In this regard, Authority has noted that all interested parties and user of the product was asked to respond within stipulated period of 40 days. However PHL had not availed the opportunity and responded by providing information within the stipulated time. The Authority holds that the interested parties and users if submit the information after the stipulated time, it becomes time barred.

G. Methodology for Calculation of Dumping Margin**G.1 Views of the domestic industry**

17. The domestic industry has claimed China to be treated as a non-market economy. They have provided a detailed note on 15 mandatory conditions prescribed under the Rules, each one of which an intending exporter has to satisfy in order to claim market economy treatment and the information and evidence relevant and necessary to establish such a claim. Applicants have claimed that unless the responding Chinese exporters conform to these standards, the Designated Authority is required to determine normal value in accordance with Para 7 of Annexure-I to the Rules.

G.2 View of exporters/importers and other interested parties

18. None of the exporters, importers, consumers and other interested parties has filed any comment or submissions with regard to normal value.

G.3 Examination by the Authority

19. The Authority sent copies of exporter's questionnaire and questionnaire on market economy treatment to exporters in China PR, however, no exporter responded to the initiation notification and provided any information. In absence of any information, the presumption of non market economy as per para 8(2) of Annexure 1 of the AD Rules remain unrebutted. The authority, therefore, has determined the normal value in accordance with para 7 of the above said annexure. In absence of any information, the Authority has determined the normal value by adopting the method "or any other reasonable basis".

G.4 Normal Value

20. Under the circumstances, the Authority has constructed the normal value by considering the major raw materials for manufacture of Vitamin -C at the import prices to India, the consumption norms and conversion cost of the domestic industry and reasonable profit. Based on above information available, the normal value has been calculated as Rs ***/kg Or USD ***/kg by considering the average exchange rate during POI of 1USD=Rs.40.75/-

G.5 Export price

21. For determination of the Export Price, all transaction-wise data on imports relating to product under consideration provided by DGCI&S have been taken into consideration. By taking into consideration all such transactions, weighted average export price (CIF) has been calculated. To calculate the net export price, expenses on account of inland freight, ocean freight and port expenses have been adjusted.

22. Based on above methodology, the Export Price has been calculated Rs ***/kg or USD***/kg by considering the average exchange rate during POI of 1USD=Rs.40.75 /-

G.6 Dumping margin

23. Considering the normal value and export price determined as detailed above, dumping margin has been determined in respect of imports reported in India during the investigation period. The dumping margin has been determined as US\$ ***/kg and 78.3%.

H. Methodology For Injury Determination and Examination of Causal Link

H.1 Views of the domestic industry

24. The domestic industry has raised a number of arguments with regard to injury and causal link, which are summarized below. The main arguments-are that

- (a) The domestic industry was not able to utilize its capacity fully due to dumped imports.
- (b) Volume of dumped import increased. As a direct consequence, the domestic industry has been prevented from utilizing its capacities.
- (c) The imports were undercutting the prices of the domestic industry. Consequently, in the event of revocation of anti dumping duties, the domestic industry would not be able to charge its present prices. This would be a situation where the domestic industry is looking for upward increase in the selling prices (due to increase in input costs). Thus, the import would force the domestic industry to reduce its prices in a situation where the domestic industry is looking for upward increase in the prices.
- (d) The potential volume of imports in the event of revocation of ADD is higher. Increase in volume of imports would imply proportionate potential decline in the sales of the domestic industry. Revocation of ADD would therefore result in decline in sales (and consequently production, capacity utilization and productivity) of the domestic industry. Inventory levels with the domestic industry would consequently increase.
- (e) Potential decline in production in the event of revocation of ADD would lead to increase in losses suffered by the domestic industry. Revocation of ADD would therefore result in deterioration in profits and consequently return on investment and cash flow.
- (f) Potential decline in selling price in the event of revocation of ADD would lead to increase in losses suffered by the domestic industry. Revocation of ADD would therefore result in deterioration in profits and consequently return on investment and cash flow.
- (g) Potential decline in sales, production, capacity utilization, profits, return on investment, cash flow, etc. would lead to negative growth of the domestic industry.

H.2 Views of exporters, importers, users etc

25. No response was provided by any exporters/importers after initiation of the Sunset Review. However, after the public hearing, comments on the injury to the domestic industry was submitted by M/s. Piramal Healthcare Limited. For the purpose of analysis of injury parameters, the Authority has not relied upon the statements of the domestic industry but has relied upon the verified data of the domestic industry.

H.3 Examination by the Authority

26. The Authority has taken note that for the sunset review, the relevant provisions of Section 9(A)(5) of the Customs Tariff Act read as under

"The anti-dumping duty imposed under this section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension."

27. Rule 23 of the Anti-dumping Rules provide for procedure for conducting sunset review. For conducting the review, the provisions of Rule 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 have been made applicable. The Authority notes that as per Rules, present state of injury is to be assessed in the sunset review.

28. In this regard Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products, with regard to the volume effect of the dumped imports. The authorities are required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

29. For the purpose of assessing present state of injury, Annexure II to the Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry.

including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Examination of performance of the domestic industry is as under

30. For the purpose of assessing present state of injury, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

(A) Volume Effect. *The effects of volume of dumped imports from subject country has been examined as follows:*

(i) Assessment of demand

31. For the calculation of the domestic consumption/demand of the product under consideration, the Authority added the sales volume of the domestic industry to the total imports into India.

Unit in MT	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (POI)
Sales of Domestic industry	316	405	665	837
Total Imports	301	239	526	295
Demand	617	644	1191	1132

The Authority notes that the demand has shown a positive trend and grew over the injury period. From the base year (2004-05) it grew by 83% in the POI..

(ii) Import volumes and market shares

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (POI)
Imports (MT)				
From China	46	41	106	103
Other countries	255	198	420	192
Total imports	301	239	526	295
Market share in imports (%)				
China	15	17	20	35
Other countries	85	83	80	65
Demand (MT)	617	644	1191	1132
Market share in demand (%)				
China	7.45	6.37	8.90	9.10
Other countries	41.33	30.74	35.26	16.96
Domestic industry	51.22	62.89	55.84	73.94

32. For the purpose of injury analysis, all imports from the subject country has been taken as dumped imports. From the data, it has been noted that:

- a) The volume of dumped imports increased significantly between 2004-05 to 2006-07. The volume declined in 2007-08, however there is an increase in volume in the POI as compared to the base year.
- b) Share of subject country in the total imports increased significantly over the injury period.
- c) The market share in demand in respect of subject country which was only 7.45% during 2004-05 increased to 9.10 % in POI.

(iii) **Production, sales, capacity and capacity utilization**

33. Production, sales, capacity & capacity utilization of the domestic industry moved as shown below:-

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Capacity	Mt	600	720	1,170	1,440
Trend		100	120	195	240
Production	Mt	507	571	841	1,009
Trend		100	113	166	199
Capacity utilization	%	84.44	79.24	71.91	70.05
Unutilized Capacity	Mt	93	149	329	431
Sales of Domestic industry	Mt	316	405	665	837
Trend		100	128	210	265

34. The capacity of the domestic industry increased from 600 MT in base year to 1440 MT in the POI. The production increased from 507 MT to 1009 MT during the same period. Similarly, the domestic sale of the domestic industry also increased from 316 MT to 837 MT during the same period. The capacity utilization declined from 84% to 70% but it is noted that the capacity of the domestic industry increased as a result of entry of M/s Bajaj Healthcare in 2006-07. It is further noted that domestic industry still has unutilized capacity in the POI.

(iv) **Price effect of the dumped imports on the Domestic Industry**

35. The impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting and price underselling, if any. For the purpose of this analysis, weighted average Net Sales Realisation (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry (worked out on the basis of the costing information of the domestic industry) have been compared with the landed value of imports from the subject country.

(a) **Price undercutting**

36. In order to ascertain the price undercutting being caused by the dumped imports, the Authority has compared net sales realization of the domestic industry with the landed price of imports. The net sales realization was arrived after deducting all rebates and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of subject imports. The landed value of imports has been compared with net sales realization of the domestic industry and it has been found that the dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry.

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
CIF export price from China Rs/Kg	207	207	169	290
Landed value of imports from China Rs./Kg	261	251	196	322
Net sales realization (Rs/Kg)	***	***	***	***
Indexed	100	81	90	115
Cost of sales (Rs/Kg)	***	***	***	***
Indexed	100	86	95	140
Price undercutting Rs/kg	***	***	***	***
Price Undercutting Range %	***	***	***	***

37. It is noted that the dumped imports were undercutting the prices of the domestic industry in the market. The price undercutting continues throughout injury period were in the range of 15-40%. For POI, undercutting was in range of 20-30%.

(b) **Price underselling**

Net Sales Realisation (Rs/kg)	***
Non Injurious Price (Rs./kg)	***
Price Underselling (China PR)	***
Price Underselling (%)	***
Price Underselling range	10-15

38. The price underselling is an important indicator of assessment of injury; thus, the Authority has worked out a non injurious price and compared the same with the landed value of dumped imports to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producer by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The analysis shows that the underselling from China PR was in the range of 10-15%.

1948 GI/09-5

(v) **Examination of other Injury Parameters**

39. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed hereunder:-

(a) **Profits and Actual and Potential Effects on Cash Flow**

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08(POI)
Cost of sales (Rs/Kg)	Rs/kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	86	95	140
Net sales realization (Rs/Kg)	Rs/kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	81	90	115
Profit/(Loss) per unit	Rs/kg	***	***	***	***
Trend		100	(139)	(165)	(1027)
Profit/(Loss) (PBT)	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend		100	(178)	(347)	(2721)
Profit/(Loss) (PBIT)	Rs/Lacs	***	***	***	***
Index		100	(37)	22	(901)
Cash profits	Rs/Lacs	***	***	***	***
Trend		100	42	118	(329)

40. The data shows that cost of sale increased by 40% (Rs.141/kg) in POI as compared to base year. The net sales realization increased by 15% (Rs.54/kg) during the same period. The profit per unit which was positive in the base year turned negative and it was -80(indexed) in POI as compared to 100 of the base year. Profits (PBIT) similarly turned negative in POI. It was -901(indexed) in the POI as compared to 100 of the base year.

41. Instead of cash flow trend, the cash flow profits of the domestic industry has been assessed and the trend indicates that it turned negative in POI. It was -329 in POI as compared to 100 of the base year.

(b) **Employment, wages and productivity**

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Number of employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	109	111	114
Wages	Rs/Lacs	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	131	249	474
Wages per unit of production	Rs/Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	116	150	238
Productivity	MT/day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	113	166	199

42. Both the companies are multi product companies. Bajaj Health care Ltd has commenced the production in 2006-07 only. Number of employees has increased by 14% in POI as compared to base year. The wages also increased considerably during POI as compared to base year.

(c) Inventories

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
Average stock	Mt	***	***	***	***
Trend	Mt	100	88	414	521

43. Average stock of finished products with the domestic industry showed increasing trend. In terms of sale days it increased from 1.29 days in base year to 2.35 days in POI.

(d) Return on Investment and Ability to Raise Capital

Particulars	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Net Fixed Assets	Rs. Lacs	***	***	***	***
Working Capital	Rs. Lacs	***	***	***	***
Capital Employed-NFA Basis (Total)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	121	238	248
Return on Capital Employed (Domestic)	%	***	***	***	***
Trends	Indexed	100	(147)	(146)	(1095)

44. The data shows that the capital employed increased by 148% in POI as compared to base year. The increase in capital employed was on account of increase in net fixed asset as well as working capital. The return on capital employed which was positive in the base year turned negative in 2005-06 and continued thereafter.

(e) **Growth**

45. Large number of the injury parameters show adverse trend during the injury period

(f) **Magnitude of dumping Margin**

46. The Authority has found significantly positive dumping margin in case of imports from China. The producers/exporters from China continued to dump their material in the Indian market even after imposition anti dumping duties. In fact, level of dumping margin is still very significant, as may be seen from the table below.

I. **Conclusions on Injury**

47. The demand of the subject goods has been growing over the injury period i.e. from 2004-05 to 2007-08. It grew by 83% in POI as compared to the base year.

48. The domestic industry has added capacity in 2005-06, 2006-07 and POI and has increased it to 1440 MT from 600 MT. The production has doubled during the same period. The sale also increased to 837 MT from 316 MT. The market share of domestic industry improved to 74% from existing 51% indicating that domestic industry has taken advantage of the growth of demand in the market.

49. The Authority has noted that the profile of the producers have been changed since imposition of the anti-dumping duty. The producers who constitute the domestic industry in the original period of investigation could not sustain and left the market. Earlier Ambalal Sarabhai was producer, however, now it no longer in the production. In this context, it has been noted that earlier M/s Bajaj Health Care Ltd. was trader, however, now it has become producer of the subject goods. This trend indicates that the producers of the subjects goods are facing serious difficulties in continuing in the business.

50. During the injury period, cost of sale has increased by 40% (Rs.141/kg.) whereas selling price increased by 15%(Rs.54/kg.). The profit/loss per unit turned to loss in 2005-06 from profit in the 2004-05. The position deteriorated further in 2006-07 and 2007-08. The return on capital employed was -1095(indexed) from 100(indexed) in the 2004-05.

51. The continuous losses of the domestic industry indicate that despite increase in market share, the domestic industry continue to suffer material injury.

J. **Other factors which may be causing injury to the domestic industry**

52. The authority has also examined following known factors other than dumped imports which may have been causing or contributing injury to the domestic industry:

(a) Volume and prices of imports from other sources

Imports from other countries also constitute significant volume, however, export price from these country were far higher than that of the subject country.

- (b) Changes in the patterns of consumption:** - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have, therefore, contributed to the injury to the domestic industry.
- (c) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:** - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- (c) Developments in technology:** - Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
- (d) Export performance:** - Applicants have exported the product under consideration. The exports of the applicant has increased. The injury of the domestic industry however has been analysed for the domestic sales only. Therefore, export performance of the domestic industry cannot be considered to be contributing to the injury to the domestic industry.
- (e) Productivity:** - Productivity of the domestic industry has declined. However, this decline in productivity is due to addition of employees by Bajaj Healthcare, which has set up new facilities. In any case, even if the impact of this productivity were segregated, it would be seen that the domestic industry has suffered injury.

K. Submissions by domestic industry on Likelihood of continuation or recurrence of injury

53. The domestic industry has submitted the following arguments on likelihood of continuation or recurrence of injury:-

- (a)** Dumping of the product under consideration is likely to continue. This is established by (a) significant exports already being made from China; (b) significant difference in the export volumes reported by Chinese Customs and Indian Customs, thus establishing possible circumvention and likely intensified dumping in the event of revocation; (c) global exports from China at comparable (or even lower) prices.
- (b)** The present situation is clearly suggestive that (a) the dumping would continue in the event of revocation of anti dumping duty; (b) the volumes would further increase, once the present anti dumping duties are revoked.

(c) The petitioners submit that the present level of dumping margin is 75% which is not only more than de-minimis but also significantly high. The circumstances, which were prevalent at the time of earlier investigations, are very much in existence even in the present period of investigation.

(d) Petitioners further submit that there exists no reason why the level of dumping would disappear or decrease if the measures were to be repealed.

(e) Following are some of the considerations, which reflect that the dumping would occur rather at aggravated level in the event anti-dumping duties are revoked or not extended for the next five years.

(i) **Exports to other countries**

54. Chinese exporters are exporting the subject goods in a large number of countries in significant volumes and at dumped prices. It is evident that in the case of revocation of anti dumping duty, dumping of Chinese material into the Country would intensify.

55. Petitioners did an analysis of exports from China to various countries. It was found that about 40,000 MT Vitamin-C was exported from China at an average price of Rs. 226 per kg., as opposed to a price of Rs. 296 per kg. for India. In fact, about 24000 MT has been exported to US alone at a price of Rs. 222 per kg. It is thus evident that the Chinese producers would have significant better business opportunities in the Indian market in the event of revocation of anti dumping duties. Given meager demand of 1400 MT, in fact, entire Indian demand can be easily catered by the Chinese producers.

(ii) **Surplus capacities with Chinese producers**

56. The significantly high capacities created by producers in China indicate that the volume of imports into India would increase significantly in the event of revocation of anti dumping duties. The petitioners could collect information with respect to the some of the producers of the subject goods in China, which shows the following position –

S.N.	Name of the Company	Capacity/Production (MT)
1	Northern General Pharmaceuticals Factory	22,000
2	Jiangsu Jiangshan Pharmaceuticals Co.	20,000
3	Hebei Welcome Pharmaceuticals	20,000
4	Weishang Pharmaceuticals (Shijiazhuang)	25,000
5	Zibo Hualong Pharmaceuticals	5,000
	Total	92,000

57. The Authority would conclude its analysis of dumping and likelihood of injury after receipt of the comments on the disclosure statement from all interested parties.

L. Causal Link, Likelihood of continuance of the recurrence of dumping and injury

58. The dumping of the subject goods from the subject country is continuing as is evident from assessment of dumping margin in earlier section of this findings. The domestic industry has pointed out the names of producers and their capacities in China PR. However, in the absence of any evidence, the statement of the domestic industry cannot be taken as facts. However, it is also noted that no producers from China PR has cooperated and provided any information/evidence about the excess capacities available in China PR. The Authority also takes note of the fact that in a anti-trust litigation in USA concerning Vitamin-C in which MOFCOM appear in the Court and taken the plea that prices by producers of Vitamin-C in China PR were controlled by the MOFCOM. Further, it has also been noted that anti-trust litigation was filed by the purchaser of Vitamin-C in USA when the Chinese manufacturers formed a cartel to fix prices and limit Vitamin-C exports to the US. In view of the fact that the dumping is continuing from the subject country and absence of any material on the record that dumping would discontinue on revocation of anti-dumping duty, the Authority holds that the dumping would continue on revocation of the anti-dumping duty.

59. The Authority has noted that the domestic industry continue to suffer material injury. The Authority further notes that producers in India are bound to sell the Vitamin-C under the Drug Price Control Order i.e. they cannot sell at the price higher than the price fixed by the NPPA. It has been submitted by the domestic industry that they have already filed application with the NPPA for revision of the price keeping in view the rising cost of production.

60. The continuance of imports from China PR at prices which undercut the domestic selling price of the domestic industry indicate that on revocation of duty, the domestic industry would be forced to match the prices of imports from China PR and would result in further deterioration of the financial performance of the domestic industry. The Authority therefore holds that the injury to domestic industry would intensify in case of revocation of the anti-dumping duty.

M. Final Findings

61. The Authority after considering the foregoing concludes that:

- a. *Subject goods originating in or exported from China PR has been exported to India below their normal value, resulting in dumping;*
- b. *The performance of domestic industry has not improved during the continuation of anti-dumping duty on the subject goods;*
- c. *And discontinuation of anti-dumping duties on the subject goods from subject country would lead to the continuation of dumping and injury to the domestic industry.*

N. Indian industry's interest & other issues

62. The purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

O. Recommendations

63. In view of positive determination of likelihood of dumping and injury on account of imports from subject country the Authority is of the opinion that continuation of the measure is required against imports from subject country. However, considering the current level of dumping from subject country and performance of the domestic industry, the Authority is of the opinion that the measure in force needs to be revised. Therefore, Authority considers it necessary and recommends anti-dumping duty on imports of subject goods from subject country in the form and manner described hereunder.

64. The Authority notes that the current anti-dumping duty is in form of reference price. However, same has not been able to prevent injury to domestic industry because of changes in cost of production and rise in prices. This situation cannot be allowed to continue as anti-dumping measures are meant for short period so that the domestic industry can cope with the challenges of the imports from subject country. In case the form of duty is not in position to adequately remove the injury of the domestic industry, it need to be changed. The domestic industry has requested that the anti-dumping duty may be recommended as a fixed duty as rise in prices of raw material (2-KGA) would make duty in form of reference price as meaningless. The Authority therefore has acceded to the request of the domestic industry and recommend that the duty may be imposed as a fixed duty.

65. Having regard to the lesser duty rule followed by the authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the margin of dumping or margin of injury whichever is lesser, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority, therefore, recommends definitive antidumping duty equal to the amount indicated in Column-9 of the table below to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject country

Sl. No	Tariff Item	Description of Goods	Grade	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of Measure	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2936.27	Vitamin-C	Any	China PR	China PR	Any	Any	3.99	Kg	USD
2	Do	Do	Do	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	3.99	Kg	USD
3	Do	Do	Do	Any	China PR	Any	Any	3.99	Kg	USD

* the anti-dumping duty is applicable to all synonyms of Vitamin-C. However, most commonly used synonyms of Vitamin-C are ascorbic Acid, L-Xyloascorbic Acid, 3-Oxo-L-gulofuranolactone (enol form), L-3-Ketothreohexuronic Acid Lactone, etc., as described under entry number "867 of Merck Index

66. An appeal against this order, after its acceptance by the Central Government, shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

R. GOPALAN, Designated Authority